

(ग) केन्द्र सरकार ने इन हथियारों को रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं, यदि कोई प्रयास नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिष कुबेरजी शर्माजी) : (क) और (ख) सरकार को श्रीलंका जन क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के खिलाफ हिंसा की खबरों की जानकारी है तथा सरकार इस बारे में चिन्तित है। श्रीलंका की सरकार ने तथाकथित अधिकांश वारदातों में अपने सुरक्षा बलों का हाथ होने से इनकार किया है। सरकार को 1 अगस्त, 1996 में भारतीय नौकाओं पर कायरता की 30 वारदातों के संबंध में समाचार प्राप्त हुए हैं। इन वारदातों में 15 मछुआरों की मृत्यु हुई है तथा 43 अन्य मछुआरों घायल हुए हैं। श्रीलंका की सरकार ने इन, तथाकथित वारदातों में में केवल 5 में अपनी नौसेना का हाथ होने की बात स्वीकार की है। जिसमें चार मछुआरों की मृत्यु हुई है तथा नौ अन्य मछुआरों घायल हुए हैं। श्रीलंका की सरकार ने सूचित किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा अल्प संख्या में विवाद समाप्त करने के लिए निर्यात सदैव मौके को तलाश में रहता है।

(ग) भारतीय मछुआरों के सामने आई समस्याओं को श्रीलंका की सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है। दोनों ही पक्ष इन समस्याओं को निपटाने में मानवीय तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। श्रीलंका की सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उन्होंने अपने सुरक्षा बलों को निर्देशित की है कि श्रीलंका के जल क्षेत्र में भटके हुए भारतीय मछुआरों के साथ व्यवहार में इष्टतम संयम बरता जाए। तथापि, श्रीलंका की सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि श्रीलंका जन क्षेत्र में देश के उत्तरी भाग के आसपास सुरक्षा की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने अपने जनक्षेत्र से निर्यात की हिंसक गति-विधियों का भी हवाला दिया है। इन वारदातों के संबंध में जिनमें श्रीलंका की नौसेना की संलिप्तता स्वीकार की गई है, यह बताया गया है कि ये वारदातें या

तो उस समय हुई हैं, जब श्रीलंका के समुद्री किनारों के समीप, श्रीलंका के जल क्षेत्र के संबन्धनशील क्षेत्रों में पाए जाने के बाद संबंधित नौकाओं ने चेतावनी की परवाह नहीं की थी। अथवा संभवतः श्रीलंका के सुरक्षा बलों और निर्यात के बीच परस्पर गोलबाजी के दौरान ये वारदातें हुई हों।

भारत ने हाल की उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान अपने मछुआरों के विरुद्ध हुई हिंसा की वारदातों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। श्रीलंका के एक शिष्टमण्डल के साथ भी विचार-विमर्श किया था, जिसके दौरान इस प्रकार की वारदातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक क्रिया-विधि संबंधी आवश्यकता को दोहराया गया है।

#### Pakistan's Readiness to sign nuclear arms Treaty with India

2499. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Hindu dated, the 27th July, 1997, under the caption 'Pak ready to sign N-arms treaty with India'.

(b) if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether Government are aware of the Pakistan statement to the effect that Islamabad was collaborating with China in the defence field, particularly on hi-tech tanks: and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI KAMLA SINHA): (a) and (b) Yes, Sir. The dialogue with Pakistan has been resumed at the Foreign Secretary level and following the last round of discussions in Islamabad, a Joint Statement was issued which envisage discussions on "peace and security" issue-

(c) and (d) Government are aware of collaboration between Pakistan and Chifla in a number of defence related projects including that relating to the development of a Main Battle Tank MBT 2000 (Aikhalid). Government have been engaged in bilateral and multilateral fora, its concern at the continuing supply by China of sophisticated weapons and related technology to Pakistan beyond its legitimate requirements. Government have made it clear that this poses a threat to India's security and is not conducive to the maintenance of peace and stability in the region. Government have been taking necessary steps to safeguard the security and national interest and will continue to do so in keeping with its assessment of developments pertaining to India's security environment.

#### **Fake travel and telephone bills in ICCR**

2500. SHRI RAINATH SINGH  
'SURYA: SHRI S. MUTHU  
MANI.

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

whether Government are aware of fake travel and telephone bills in the ICCR:

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
(SHRIMATI KAMLA SINHA): (a) No,  
Sir. There is no such "racket in fake tra-  
vel or telephone bills" in the ICCR. The  
Council's accounts are audited every year  
by the Comptroller & Auditor General  
of India and such irregularities have not  
been indicated by them. Additionally, the  
latest report of the Standing Committee  
on External Affairs of Parliament which

was into the working of the ICCR, details has no reference to such a racket in Travel and Telephone bills.

(b) Not applicable.

(c) Not applicable.

(d) Not applicable.

(e) Question does not arise.

#### **India-Bhutan bilateral ties**

2501. SHRIMATI JAYANTI PAT-  
NAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the areas in which India has been able to have established bilateral ties

(b) whether any joint agreement has been the areas of common interest to both the countries

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
SHRI SALEEM IQBAL SHERWAN

(a) the basic framework of bilateral relations between India and Bhutan in the treaty of friendship and cooperation. Bilateral economic cooperation has been established between India and Bhutan in the areas of hydro power, geological, agricultural, technical cooperation, air, construction, road, construction, electrical, distribution, mining, health, education and telecommunication. India is the principal donor of aid for the economic development of Bhutan.

(b) The India-Bhutan Trade and Commerce Agreement was renewed in February 1995 and is effective for a five year period from March 1995. Other agreements signed between the two countries include those relating to (1) implementation of the Jaldhaka Hydro-electric Project in September 1961; (2) exchange of postal parcels in December 1970; (3) Chukha Hydro-electric Project.